सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 26 JUNE TO 02 JULY 2026 • VOLUME 47 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

प्रेरणा

"सपनों की दूरी कदमों से नहीं, हिम्मत से तय होती है।"

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	38°	27°
शनिवार	38°	29°
रविवार	39°	29°
सोमवार	39°	29°
मंगलवार	39°	29°
बुधवार	37°	28°
वीरवार	36°	28°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY
CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?
What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost
E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

पश्चिम एशिया में हालात सुधरने से इंडस्ट्री को राहत

केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी की सभी पाबंदियां हटाईं

नई दिल्ली. इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एलपीजी ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने गुरुवार को नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर लगी सभी सेक्टर-वाइज़ पाबंदियां हटा दीं और सप्लाई को वेस्ट एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया। इसके अलावा, संकट की शुरुआत में रोकी गई बल्क एलपीजी की सप्लाई में भी ढील दी गई है और इसे संकट से पहले की खपत के स्तर का 50% कर दिया गया है जिससे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों को काफी राहत मिली है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि नॉन-एलपीजी इस्तेमाल के लिए सी3-सी4 स्ट्रीम का बढ़ा हुआ आवंटन इस तरह लागू किया जाएगा कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर कोई असर न पड़े और देश में एलपीजी का कुल उत्पादन हर दिन कम से कम 40 टीएमटी बना रहे। पश्चिम एशिया संकट के दौरान, सरकार ने 'ज़रूरी चीज़ों के कानून' के तहत प्रावधान लागू किए थे और निर्देश दिया था कि सी3-सी4 हाइड्रोकार्बन स्ट्रीम का इस्तेमाल सिर्फ़ एलपीजी बनाने के लिए किया जाए। इस कदम से इन फीडस्टॉक को पेट्रोकेमिकल और दूसरे डाउनस्ट्रीम उद्योगों से हटाकर एलपीजी के घरेलू उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया गया, ताकि देश में एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

सप्लाई की स्थिति में सुधार होने के बाद सरकार ने अब एलपीजी पूल के लिए सी3-सी4 स्ट्रीम के डायवर्जन को कम करने और पेट्रोकेमिकल व अन्य अहम सेक्टरों के लिए इनका आवंटन बढ़ाने का फ़ैसला किया है। मंत्रालय के अनुसार, गैर-एलपीजी इस्तेमाल के लिए सी3-सी4 स्ट्रीम का बढ़ा हुआ आवंटन घरेलू एलपीजी उपलब्धता पर असर डाले बिना लागू किया जाएगा। देश में एलपीजी का उत्पादन कम से कम 40 हज़ार मीट्रिक टन (टीएमटी) प्रतिदिन बनाए रखा जाएगा।

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा फीस में हुआ बड़ा बदलाव

सरकार ने गुरुवार को लगभग 14 साल में पहली बार पासपोर्ट फीस बढ़ाई है। 1 जुलाई से नए पासपोर्ट की कीमत नॉर्मल स्कीम के तहत 2,500 रुपये और तत्काल स्कीम के तहत 5,000 रुपये हो जाएगी। यह नई फीस लिस्ट विदेश मंत्रालय (एमईए) के उस स्पष्टीकरण के एक दिन बाद जारी की गई, जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज़ है, न कि भारतीय नागरिकता का सबूत। नई दरों के तहत, 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए नया 36-पेज का पासपोर्ट या उसे दोबारा जारी करवाने का खर्च नॉर्मल स्कीम में 1,500 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये हो जाएगा, जबकि तत्काल फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। खोए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलवाने के लिए भी आवेदकों को काफी ज़्यादा पैसे देने होंगे। 36-पेज वाले पासपोर्ट को बदलवाने की कीमत अब नॉर्मल स्कीम के तहत 5,000 रुपये और तत्काल स्कीम के तहत 7,500 रुपये होगी, जबकि 60-पेज वाले पासपोर्ट को बदलवाने की कीमत क्रमशः 6,000 रुपये और 8,500 रुपये होगी। 18 साल से कम उम्र के आवेदकों के लिए, नया या दोबारा जारी होने वाले 36-पेज के पासपोर्ट की कीमत नॉर्मल स्कीम के तहत 1,750 और तत्काल स्कीम के तहत 4,250 होगी। नाबालिगों के खोए या खराब हुए पासपोर्ट को बदलने की फीस नॉर्मल कैटेगरी में 4,250 और तत्काल कैटेगरी में 6,750 तय की गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बदली हुई फीस का नियम 1 जुलाई या उसके बाद जमा किए गए सभी पासपोर्ट आवेदनों पर लागू होगा।

हम फर्जी वीडियो के पीछे की सच्चाई श्री अकाल तख्त साहिब के सामने रखेंगे : सीएम भगवंत मान

बोले- किसी अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जैसा दिखाने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया गया था

• **जालंधर ब्रीज.** मोहाली

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने गुरुवार को सबूत पेश करते हुए धर्म के आधार पर उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल की गई एक कथित फर्जी वीडियो के पीछे रची गई साजिश का पर्दाफाश किया। मीडिया के सामने वीडियो और अन्य सामग्री दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जैसा दिखने वाला एक मास्क (मुखौटा) तैयार करवाया गया था और उसी का उपयोग इस कथित फर्जी वीडियो को बनाने के लिए किया गया। उन्होंने कनाडा में रहने वाले जगमन समरा की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की, जिसके बारे में उनका कहना है कि उसने इस मास्क का उपयोग करके वीडियो शूट की थी। मान ने कहा कि यह कथित फर्जी वीडियो कनाडा के एक होटल में फिल्माई गई थी, जबकि वह वर्ष 2016 के बाद कभी कनाडा नहीं गए। उन्होंने कहा कि यह मास्क एक कार में जगमन समरा को डिलीवर किया गया था और इसके बाद समरा इसे अपने हाथ में पकड़े हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वीडियो में मास्क स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा उनकी गर्दन के ऑपरेशन का निशान भी उसमें नहीं है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने वालों की पहचान कर ली गई है और जांच पूरी होने के बाद उन्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि पूरे मामले को सबूतों सहित श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष रखा जाएगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए मान ने लिखा, "बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मेरे प्यारे पंजाबियो, पिछले कुछ दिनों से मेरे राजनीतिक विरोधियों ने मेरी एक फर्जी वीडियो पर राजनीति की है। आज एक मास्क ने उन विरोधियों के असली चेहरे उजागर कर दिए हैं। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं कि उस वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूं।"

मान झूठ का जाल बुन रहे : राजा वड़िंग

कांग्रेस ने सीएम मान के विवादित वीडियो को लेकर दी गई "मास्क" वाली सफाई को खारिज करते हुए इसे कमजोर बहाना बताया है जिसका उद्देश्य खुद का बचाव करने की एक अन्य असफल कोशिश है। पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दें और श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हों। वड़िंग ने कहा कि जितना अधिक अड़ियल रवैया मान अपना रहे हैं, इतना ही इनकी दोषी होने की बात साबित हो रही है और लोगों का यह विश्वास मजबूत हो रहा है कि यह बहुत कुछ छिपा रहे हैं।

श्री अकाल तख्त ने पंजाब के 78 विधायक और मंत्रियों 29 जून को किया तलब

अमृतसर. सिख धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था, अकाल तख्त ने पंजाब के सभी सिख विधायकों और मंत्रियों को 29 जून को अपने सामने पेश होने के लिए बुलाया है। साथ ही, गैर-सिख विधायकों और मंत्रियों को 'जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट, 2026' पर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस कानून में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ के अपमान के लिए उम्रकैद की सज़ा का प्रावधान है। यह कदम पंजाब विधानसभा द्वारा 13 अप्रैल को उस कानून को पारित करने के कुछ महीनों बाद उठाया गया है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान के मामलों में उम्रकैद और भारी जुर्माने जैसी कड़ी सज़ा का प्रावधान है। इस समन में पूरे पंजाब के 78 सिख विधायक, नौ सिख कैबिनेट मंत्री और भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार के पांच गैर-सिख कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। निर्देशों के अनुसार, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां सहित सभी 78 सिख विधायकों और नौ सिख कैबिनेट मंत्रियों को सुबह 11 बजे अकाल तख्त के सामने पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि गैर-सिख मंत्रियों और विधायकों को उसी तारीख तक लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।

उन्होंने कहा कि सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया है कि वे 29 जून को सुबह 11 बजे अमृतसर में अकाल तख्त के सामने पेश हों और कानूनी संशोधन पर चर्चा कर अपनी राय रखें। गैर-सिख कैबिनेट मंत्रियों से कहा गया है कि वे उसी तारीख से पहले लिखित रूप में अपनी राय दें। अकाल तख्त का यह कदम अहम है क्योंकि हाल के वर्षों में सिख धर्मगुरुओं ने पंजाब के बड़े राजनीतिक नेताओं से जुड़े मामलों में दखल दिया है।

10 आधुनिक हथियारों, 5 किलो हेरोइन व 30 लाख रुपये की हवाला राशि समेत सात गिरफ्तार

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/अमृतसर

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान के दौरान सीमा पार से संचालित अवैध हथियारों, नशे और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित सात आरोपियों को 10 आधुनिक पिस्तौलों, 5.048 किलोग्राम हेरोइन और 30.38 लाख रुपये की हवाला राशि सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जसप्रीत सिंह उर्फ कालू (21) निवासी गांव खुरमणियां (अमृतसर); जगजीत सिंह उर्फ जग्गी (40) मूल निवासी जलालाबाद (अफगानिस्तान), जो वर्तमान में तिलक नगर (नई दिल्ली) में रह रहा था; गोपाल शर्मा उर्फ गौरव (21) निवासी इस्लामाबाद (अमृतसर); अनीकेत सहोता (21) निवासी राम नगर कॉलोनी (अमृतसर); प्रभजीत सिंह उर्फ प्रभ (26) निवासी गुमटाला कॉलोनी (अमृतसर); तथा राजबीर सिंह उर्फ आर्यन (22) निवासी मकबूलपुरा (अमृतसर) के रूप में हुई है। इनके साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है।

बरामद किए गए हथियारों में एक 9 एमएम उजी (यूजेडआई) सब-मशीन गन (इटली निर्मित), एक गफ्फार सब-मशीन सिक्योरिटी गन (9 एमएम ऑटोमैटिक), 9 एमएम की चार ग्लॉक पिस्तौलें (ऑस्ट्रिया निर्मित), एक 9 एमएम जिगाना स्पोर्ट पिस्तौल, एक कोल्ट किंग कमांडो सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल (.30 बोर), एक स्कॉर्पियन जिगाना तिसास तुर्की पिस्तौल (.30 बोर) तथा एक अन्य .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। हथियारों, नशीले पदार्थों और हवाला राशि की बरामदगी के अलावा पुलिस टीमों ने आरोपियों का मोटरसाइकिल भी जब्त कर लिया है।

विदेश से आने वालों के लिए सरकार ने लॉन्च किया एयर सुविधा 2.0 पोर्टल

नई दिल्ली. अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला बीमारी के फैलने के बीच, एंट्री पॉइंट्स पर पब्लिक हेल्थ की निगरानी को मज़बूत करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने गुरुवार को यात्रियों के लिए एक अपग्रेडेड, कॉन्टैक्टलेस हेल्थ सेल्फ़-डिक्लेरेशन पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ द्वारा विकसित 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल, विदेश से आने वाले यात्रियों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस से पहले ज़रूरी ऑनलाइन हेल्थ सेल्फ़-डिक्लेरेशन जमा करने की सुविधा देता है। इस फ़ॉर्म में 21 दिनों की यात्रा का इतिहास, बीमारी के संपर्क में आने का इतिहास और अगर कोई लक्षण हों तो उनकी जानकारी देनी होती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस पोर्टल से एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर, ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन, आईडीएसपी और राज्य के सर्विलांस अधिकारियों के साथ रियल-टाइम डेटा शेयर किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इससे जोखिम वाले यात्रियों की तेज़ी से पहचान और उन्हें रेफर करने में मदद मिलेगी, साथ ही आने-जाने की प्रक्रिया भी आसान और कॉन्टैक्टलेस बनी रहेगी, क्योंकि लैंडिंग के बाद फ़िज़िकल फ़ॉर्म नहीं भरना होगा।

एसआईटी के सामने पेश हुए आप नेता संजय सिंह, राम मंदिर मामले के दस्तावेज सौंपे

लखनऊ: आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह बृहस्पतिवार को राम मंदिर दान में कथित अनियमितता से संबंधित मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) के सामने पेश हुए और दस्तावेज सौंपे। उन्होंने दावा किया कि उनके द्वारा सौंपे गए दस्तावेजों में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के सबूत हैं। एसआईटी का नेतृत्व लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। संजय सिंह पूर्वाह्न करीब 11 बजे कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और जांच टीम को दस्तावेज सौंपे। आप सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए दावा किया कि उनके पास कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत हैं और उन्होंने उन्हें एसआईटी को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि 13 जमीनों के दस्तावेज मैंने एसआईटी प्रमुख को दिए हैं। अब वह क्या जांच करेंगे, वह सामने आएगा। उसमें बहुत बड़े और गंभीर घोटाले हुए हैं। ऐसे तमाम मामले हैं, जिससे मालूम होता है कि जमीनों के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि दस्तावेज़ मामले के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में मदद कर सकते हैं और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे की निष्पक्ष जांच तभी संभव है, जब विभिन्न पक्षों के पास उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्य और सबूत जांच एजेंसी के सामने रखे जाएं। एसआईटी के सामने पेश होने का उद्देश्य अपना पक्ष रखना और मेरे पास मौजूद दस्तावेज जमा करना था। आप नेता संजय सिंह ने दावा किया कि दस्तावेज गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं और जांच एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच की आवश्यकता है। उनके मुताबिक, यदि दस्तावेजों की निष्पक्षता से जांच की जाए तो कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं।

नरेंद्र मोदी : सबसे लंबे समय तक 'प्रत्यमक्ष रूप से निर्वाचित' पीएम

जालंधर ब्रीज. भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता को लेकर चल रही बहस के बीच, मुझे मेरे पिता, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभूतपूर्व जीत के बारे में बताई गई एक दिलचस्प बात याद आती है। उस समय बाबा भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद, उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, जो शायद एक सच्चे लोकतंत्र की वास्तेविक पहचान है।

चुनाव परिणाम आने के बाद, मोदी जी राष्ट्रपति भवन में बाबा से मिलने आए। बातचीत के दौरान बाबा ने मोदी जी से चुनाव के बारे में उनका विश्लेषण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि तीन दशकों के बाद किसी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। तब बाबा ने अपने विशिष्टो प्रोफ़ेसर वाले अंदाज़ में पूछा, 'और क्या?' जब मोदी जी चुप रहे, तो बाबा ने बताया कि 2014 का लोकसभा चुनाव इतिहास में अनोखा था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक नया चेहरा पहले ही घोषित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी को मिला लोगों का अपार समर्थन केवल उनकी पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि यह लोगों का श्री नरेन्द्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सीधा जनादेश था। दूसरे चुनावों के विपरीत, जहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा या तो मान लिया जाता है पर आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया जाता; या परंपरा के अनुसार नवनिर्वाचित सांसद उनका चुनाव करते हैं; या यह गठबंधन के गणित से तय होता है और यह प्रक्रिया चुनाव के बाद होती है। मोदी जी से पहले डॉ. मनमोहन सिंह, जो कभी जन-नेता नहीं रहे, उन्हें तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने चुना था। भारत के दो प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव और श्री एच.डी. देवेगौड़ा - तो प्रधानमंत्री बनने के समय संसद के सदस्य भी नहीं थे। सरल शब्दों में कहें तो, प्रधानमंत्री का चुनाव वरिष्ठ राजनेता करते थे। 2014 भारतीय राजनीति के चुनावी समीकरणों में एक बहुत बड़ा बदलाव था, जहां देश की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी को लगभग 'राष्ट्रपति चुनाव' की ही तरह, स्पष्ट रूप से और बिना किसी संदेह के अपना प्रधानमंत्री चुना।

शर्मिष्ठा मुखर्जी
(लेखिका एक स्तम्भकार हैं और 'प्रणब माय फादर: अ डॉटर रिमेंबर्स' पुस्तक की लेखिका हैं। वह वर्तमान में 'प्रणब मुखर्जी लिगेसी फाउंडेशन' की संचालक हैं।)

उल्लेखनीय है कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी 'राष्ट्रीय' राजनीति में नए थे। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लंबे कार्यकाल के दौरान अपनी एक विशिष्टर पहचान बनाई थी, लेकिन 2014 उनका पहला लोकसभा चुनाव था। यह एक अनोखी बात है कि पहली बार सांसद बनने वाले व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार संसद भवन में प्रवेश किया। (पुरानी) संसद की सीढ़ियों पर 'प्रणाम' करने का उनका भावुक कदम हृदय को छू लेने वाला ऐसा क्षण था, जिसने करोड़ों भारतीयों के हृदय में अपनी जगह बना ली।

नरेंद्र मोदी न केवल देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बल्कि शायद स्वचतंत्रता के बाद देश ने जितने भी प्रधानमंत्री देखे हैं, उनमें से वे सबसे मज़बूत नेताओं में से एक हैं। वे गठबंधन सरकारों, जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं, के उन व्यासवधानों का शिकार हुए बिना एक मज़बूत और स्थिर सरकार देने में सफल रहे हैं। कोई उनकी कई नीतियों या काम करने के तरीके से असहमत हो सकता है और लोकतंत्र में ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है; लेकिन कोई भी उनके करिश्मे और 'आकांक्षी भारत' के लिए प्रेरणा के तौर पर भारतीय मतदाताओं के साथ उनके जुड़ाव को नकार नहीं सकता। यह बात 2019 और फिर 2024 में भी स्पकष्टन रूप से दिखी। आप श्री नरेन्द्र मोदी को पसंद करें या नापसंद, लेकिन आप 'ब्रांड मोदी' की अनदेखी नहीं कर सकते। बड़ी ताक़त के साथ बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है। एक आम नागरिक के रूप में, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वे लोगों से प्राप्त भारी जनादेश के साथ पूरा न्याय करें और हमारे देश को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएँ।

अमेजन का भारत में 48 अरब डॉलर का मेगा इन्वेस्टमेंट, पीएम मोदी बोले- युवाओं के लिए खुलेंगे नए मौके

नई दिल्ली. अमेज़न के रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि दुनिया भर में भारत में निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। यह बयान नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और अमेज़न के सीईओ एंडी जैसी के बीच हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद आया, जिसमें इस बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने घोषणा की कि वह 2026 और 2030 के बीच भारत में 48 अरब डॉलर की पूंजी लगाएगी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया कि मिस्टर एंडी जैसी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही। मैं भारत में अमेज़न के रिकॉर्ड 48 अरब डॉलर के निवेश का स्वागत करता हूँ। इससे हमारे युवाओं के लिए नए मौके बनेंगे। साथ ही, इससे पता चलता है कि दुनिया भर में भारत में निवेश करने में दिलचस्पी बढ़ रही है। जैसी ने आगे कहा हमने 2010 से भारत में 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। और फिर पिछले साल के आखिर में हमने घोषणा की थी कि हम 2026 और 2030 के बीच भारत में 35 अरब डॉलर का और निवेश करेंगे। और आज हमने घोषणा की है कि हम उस रकम को 35 अरब से बढ़ाकर 2026 और 2030 के बीच कुल 48 अरब डॉसक का निवेश करेंगे।

गुजरात का रहस्यमयी शिव मंदिर, जो हर दिन दो बार समा जाता है समुद्र की गोद में

Travelling भारत में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं, जो अपनी खूबसूरती और अनोखी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। इसी में से एक है गुजरात में बना स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर दिन में 2 बार पानी में समा जाता है और फिर ऊपर आ जाता है।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जो अपनी खूबसूरती, इतिहास और अनोखी विशेषताओं के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। आज हम आपको जिस मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, वह गुजरात में है और उसे गायब मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।

गुजरात के भरूच जिले के छोटे से गांव कवी कंबोई में स्थित है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव विराजमान है और उनके शिवलिंग की लोग पूजा करने पहुंचते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये पानी की लहरों के बीच छिप जाता है और ऐसा दिन में करीब दो बार होता है। जब मंदिर पानी में होता है, तब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। ऐसा कहा जाता है कि कभी-कभार शिवलिंग दिखती है। ऐसा क्यों होता है और इसके दर्शन करने लोग कैसे जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं।

क्यों कहा जाता है गायब मंदिर

स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को लोग गायब मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका ये नाम पानी में डूबने की वजह से ही पड़ा है। मंदिर की विशेषता यही है कि ये पानी की लहरों में दो बार डूब जाता है और फिर कुछ घंटों के बाद दिखाई देने लगता है। उस समय मंदिर की दीवारें, खंभे और गर्भगृह तक पानी के नीचे चले जाते हैं, सिर्फ शिवलिंग कभी-कभी दिखता है।

ज्वार-भाटा का खास महत्व

इस मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन करने से पहले ज्वार-भाटा का समय देखना पड़ता है। ज्वार (High Tide) जब समुद्र का पानी किनारे की ओर बढ़कर जलस्तर ऊंचा कर देता है और भाटा (Low Tide), जब पानी पीछे हटता है और जलस्तर नीचे चला जाता है। भाटा के समय में ही मंदिर वापिस ऊपर आ जाता है। इसलिए यहां पर श्रद्धालु ज्वार से कुछ घंटे पहले आते हैं, जिससे वह ये अद्भुत नजारा देख सकें। इस मंदिर के दर्शन सिर्फ लो टाइड के दौरान ही किए जा सकते हैं।

शिवलिंग का अभिषेक भी है खास

भगवान शिव का जलाभिषेक आपने हमेशा दूध से किया होगा लेकिन इस स्तंभेश्वर महादेव मंदिर में सरसों के तेल से उनका अभिषेक किया जाता है। यहां पर आने वाले भक्त सरसों का तेल कटोरी में लेकर आते हैं और वही शिवलिंग पर चढ़ाते हैं।

मंदिर का पौराणिक इतिहास

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध करने के बाद आत्मिक शांति के लिए तीन शिवलिंग स्थापित किए थे। ऐसी मान्यता है कि स्तंभेश्वर महादेव उन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है। यही कारण है भगवान शिव के दर्शन के लिए लोग दूर से आते हैं। कहा जाता है यहां आए भक्तों की हर मुराद पूरी होती है।

Ai प्रतिकात्मक तस्वीर

कैसे पहुंचे

स्तंभेश्वर महादेव मंदिर वडोदरा से करीब 75 किमी दूर है। वडोदरा तक आने के बाद आप वहां से कैब या टैक्सी बुक करके मंदिर तक जा सकते हैं। आने से पहले ज्वार-भाटा का समय जरूर पता कर लें।

LIFESTYLE

इसलिए हाई स्टैंडर्ड वाले लोग रहते हैं आगे, ये 5 आदतें उन्हें बनाती हैं दूसरों से खास!

हाई स्टैंडर्ड का मतलब सिर्फ महंगी चीजें खरीदना नहीं होता। असली पहचान आपकी सोच, आदतों और रोजमर्रा के फैसलों से बनती है। आइए जानते हैं ऐसी बातें जो हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों को भीड़ से अलग बनाती हैं।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

हाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या है?

जब लोग 'हाई स्टैंडर्ड' सुनते हैं तो अक्सर महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी लाइफस्टाइल की कल्पना कर लेते हैं।

लेकिन असल में हाई स्टैंडर्ड का मतलब खुद के लिए बेहतर सोच, बेहतर आदतें और सही चुनाव है। ऐसे लोग हर दिन अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति को महत्व देते हैं। वे दूसरों से ज्यादा खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। उनकी छोटी-छोटी आदतें ही उन्हें खास बनाती हैं।

1. छोटी परेशानियों में घबराते नहीं : किसी मीटिंग का लेट होना, ट्रैफिक में फंस जाना या कोई छोटी गलती हो जाना- ऐसी चीजें हर किसी के साथ होती हैं। लेकिन हाई स्टैंडर्ड वाले लोग इन बातों पर जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होते।

वे तुरंत रिएक्ट करने की बजाय स्थिति को समझते हैं और समाधान ढूंढ़ते हैं। क्योंकि उनकी जिंदगी लगातार तनाव और जल्दबाजी में नहीं चलती। वे जानते हैं कि हर छोटी परेशानी पर घबराने से समस्या नहीं, बल्कि स्ट्रेस बढ़ता है।

2. उन्हें क्वालिटी आसानी से नजर आती है : ऐसे लोग हर चीज में सिर्फ कीमत नहीं देखते, बल्कि उसकी क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। चाहे बात किसी किताब की हो, कपड़ों की हो, काम की हो या रिश्तों की।

वे अच्छी चीजों को पहचानना सीख लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरों को जज करते हैं। बल्कि वे अपने आसपास मौजूद अच्छी चीजों और बेहतरीन काम की कद्र करना जानते हैं। यही आदत उनके फैसलों को और बेहतर बनाती है।

3. उनका लुक हमेशा सोच-समझकर चुना हुआ लगता है : हाई स्टैंडर्ड वाले लोग सिर्फ खास मौकों पर ही अच्छे नहीं दिखते। वे रोजमर्रा की जिंदगी में भी साफ-सुथरे और व्यवस्थित नजर आते हैं।

इसका मतलब महंगे कपड़े पहनना नहीं है। वे बस इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका पहनावा, व्यवहार और व्यक्तित्व संतुलित दिखे। वे जानते हैं कि खुद को सम्मान देना भी आत्मविश्वास का एक हिस्सा है। इसलिए उनका स्टाइल हमेशा सहज और आकर्षक लगता है।

4. उनकी पसंद होती है, जिद नहीं : जो लोग सच में हाई स्टैंडर्ड रखते हैं, उन्हें बार-बार अपनी पसंद या स्टेटस साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे जानते हैं कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं।

लेकिन वे हर बात पर अपनी शर्तें नहीं थोपते। उनकी पसंद स्पष्ट होती है, लेकिन वे दूसरों की पसंद का भी सम्मान करते हैं। यही वजह है कि वे आत्मविश्वासी लगते हैं, अहंकारी नहीं। उनकी सादगी ही उन्हें खास बनाती है।

5. रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर बनाने पर खर्च करते हैं : ऐसे लोग सिर्फ दिखावे वाली चीजों पर पैसा खर्च नहीं करते। वे उन चीजों में निवेश करना पसंद करते हैं जो उनकी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाएं।

जैसे अच्छी नींद के लिए आरामदायक गद्दा, सीखने के लिए किताबें, स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना या समय बचाने वाले साधन। वे समझते हैं कि असली लग्जरी रोज की जिंदगी में आराम और संतुलन महसूस करना है।

वे अपनी ऊर्जा की भी कीमत समझते हैं : हाई स्टैंडर्ड वाले लोग सिर्फ पैसे ही नहीं, अपनी ऊर्जा और समय को भी महत्व देते हैं। वे हर बहस, हर ड्रामे और हर नकारात्मक माहौल का हिस्सा नहीं बनते। वे सोच-समझकर तय करते हैं कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। यही आदत उन्हें मेंटली शांत और ज्यादा फोकस्ड बनाए रखती है। वे जानते हैं कि जहां ध्यान जाता है, वहीं जीवन की दिशा भी जाती है।

छोटी आदतें बनाती हैं बड़ा फर्क : हाई स्टैंडर्ड का संबंध बैंक बैलेंस से कम और सोच से ज्यादा होता है। छोटी-छोटी आदतें जैसे शांत रहना, क्वालिटी को महत्व देना, खुद का सम्मान करना और समझदारी से फैसले लेना, किसी भी व्यक्ति को बेहतर बना सकती हैं। ये आदतें रातोंरात नहीं बनतीं, लेकिन धीरे-धीरे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। यही वो चीजें हैं जो किसी इंसान को भीड़ से अलग और यादगार बनाती हैं।

डिस्क्लेमर : इस लेख में किए गए दावे यूट्यूब वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं। जालंधर ब्रीज इसकी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

साधारण तवा पर बनाएं रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी चिकन, इस वायरल ट्रिक से मिलेगा स्मोकी फ्लेवर

चिकन लवर्स को तंदूरी चिकन खाना भी काफी पसंद होता है और अक्सर रेस्टोरेंट में वहीं ऑर्डर किया जाता है। अब आप कहेंगे कि घर पर बिना तंदूर के चिकन तंदूर कैसे बनाएं? तो चलिए आज हम आपको बिना तंदूर के स्मोकी फ्लेवर वाला तंदूरी...

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं, तो तंदूरी चिकन भी जरूर पसंद करते होंगे। रेस्टोरेंट में मिलने वाले तंदूरी चिकन में तेल कम होता है और उसका स्मोकी फ्लेवर स्वाद को और बढ़ा देता है। इसे देखकर अक्सर लगता है कि बिना ज्यादा तेल के ही इसे बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। हालांकि, होटल जैसा टेस्टी तंदूरी चिकन घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हर किसी के पास तंदूर नहीं होता। लेकिन तवा तो हर किसी के घर में होता है। सोशल मीडिया पर तवा पर तंदूर चिकन बनाने की आसान रेसिपी खूब वायरल हो रही है और खास बात ये है कि तंदूर चिकन बनता भी दिख रहा है। तो चलिए आज हम भी आपको तवा स्टाइल तंदूरी चिकन की सिंपल रेसिपी बताते हैं।

तवा पर तंदूरी चिकन बनाने के लिए सामग्री

- 500 ग्राम चिकन (लेग पीस या बड़े टुकड़े)
- ½ कप दही
- 1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट
- 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस
- 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च (अच्छे रंग के लिए)
- ½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
- 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
- ½ छोटा चम्मच जीरा पाउडर
- ½ छोटा चम्मच गरम मसाला
- 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला
- 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
- स्वादानुसार नमक
- 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल (वैकल्पिक, अगर बिल्कुल बिना तेल बनाना हो तो छोड़ सकते हैं)
- 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी
- 1-2 टुकड़े कोयला (स्मोकी फ्लेवर के लिए)
- सजाने के लिए प्याज के स्लाइस, नींबू और हरा धनिया

चिकन करें मैरिनेट

सबसे पहले तो आपको चिकन के पीस को पानी से अच्छे से धोकर रख लेने हैं। अब इन पीस पर चाकू से लंबे कट मार दीजिए, जिससे मसाला अंदर तक भर जाए। एक बड़े बाउल में दही, अदरक-लहसुन पेस्ट, नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, तंदूरी मसाला, काली मिर्च, कसूरी मेथी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इसमें चिकन डालें और मसाला सभी पीस पर अच्छी तरह कोट कर दें। इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए मैरिनेट करें।

तवा वाली ट्रिक

आप रोटी सेंकने वाला तवा ले सकते हैं या फिर जो तवा पैन आता है, जिसमें ढक्कन होता है उसे लें। तवा को पहले 5 मिनट तक प्रीहीट कर लें और बिना तेल के बना रहे हैं, तो तेल न डालें। अगर तेल डालना चाहते हैं, तो 1-2 चम्मच डालें। फिर मैरिनेट किए हुए चिकन के पीस को अलग-अलग तवा पर रखें। अब इसे ढककर 8-10 मिनट पकाएं और ऐसे ही दूसरी तरफ पलटकर पका लें। जब चिकन लगभग पक जाए, तब ढक्कन हटाकर 4-5 मिनट दोनों तरफ से तेज आंच पर सेंकें। इससे ऊपर हल्का चार्ड इफेक्ट आएगा और तंदूरी जैसा स्वाद मिलेगा।

स्मोकी फ्लेवर के लिए क्या करें

रेस्टोरेंट जैसा स्मोकी फ्लेवर पाने के लिए एक छोटा कोयला गर्म करें। उसे कटोरी में रखकर चिकन के बीच रखें, ऊपर से 2-3 बूंद घी डालें और तुरंत ढक दें। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। बस आपके चिकन में स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा लगेगा। बस फिर तैयार तंदूरी चिकन को प्याज, नींबू, हरी मिर्च, चटनी के साथ गरम-गरम सर्व करें।

ये प्यार नहीं, अपने बच्चे को कमजोर बना रहे हैं आप!

PARENTING

जालंधर ब्रीज (फीचर) . बच्चों को प्यार-दुलार देना ठीक है, लेकिन प्यार के साथ कुछ बाउंड्रीज तय करना भी उतना ही जरूरी होता है। अक्सर माता-पिता अपने बच्चों को हर परेशानी से बचाने और उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। अच्छी परवरिश का मतलब सिर्फ बच्चों को सुविधाएं देना नहीं, बल्कि उन्हें जीवन की सच्चाइयों और जिम्मेदारियों के लिए भी तैयार करना है।

अगर आपके बच्चे की हर जिद और हर मांग तुरंत पूरी हो जाती है, तो यह आगे चलकर उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। जीवन में हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार और उसी समय नहीं मिलती। ऐसे में बच्चों का यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। जब बच्चा छोटी उम्र में धैर्य रखना सीखता है, तो वह अपने इमोशंस और इच्छाओं को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाता है।

बच्चों को प्यार के साथ यह भी सिखाना जरूरी है कि हर गलत व्यवहार के लिए एक कंसीक्वेंसेस भी होता है। जब उन्हें सही समय पर सही दिशा मिलती है, तभी वे अनुशासन और जिम्मेदारी का महत्व समझते हैं।

अगर आप हर बार बच्चे का बैग तैयार करते हैं, उसकी भूली हुई चीजें पहुंचाते हैं या उसकी गलतियों को संभाल लेते हैं, तो हो सकता है कि आप उसकी मदद से ज्यादा उसका नुकसान कर रहे हों। बच्चे तभी जिम्मेदार बनते हैं, जब उन्हें अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाने का मौका मिलता है।

कई घरों में बच्चों को किसी भी घरेलू काम से पूरी तरह दूर रखा जाता है। यह सोचकर कि उनका काम सिर्फ पढ़ाई करना है। लेकिन घर के छोटे-छोटे काम बच्चों को जिम्मेदारी और मेहनत की अहमियत सिखाते हैं। अपनी प्लेट उठाना, अपना कमरा व्यवस्थित रखना या घर के किसी छोटे काम में मदद करना उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इससे वे यह भी सीखते हैं कि परिवार में हर सदस्य का कुछ न कुछ योगदान होता है।

अगर बच्चा हर असफलता के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है, तो यह आदत आगे चलकर उसके विकास में रुकावट बन सकती है। परीक्षा में कम नंबर आने पर टीचर को दोष देना या किसी गलती के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार मानना, जिम्मेदारी से बचने की निशानी है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना ही आगे बढ़ने का सही तरीका है। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना सीखते हैं, वे जीवन में ज्यादा सफल और आत्मविश्वासी बनते हैं।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

कद्दू के पत्ते आयरन की कमी करेंगे दूर, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया खाने का तरीका जिससे मिलेंगे फायदे

Health आयरन की कमी की वजह से शरीर में दर्द, कमजोरी, थकान और स्किन पर बुरा असर हो रहा तो कद्दू की पत्तियां आपकी समस्याओं को खत्म करेंगी। न्यूट्रिशनिस्ट से जानें कैसे खाएं ये हरी पत्तियां।

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

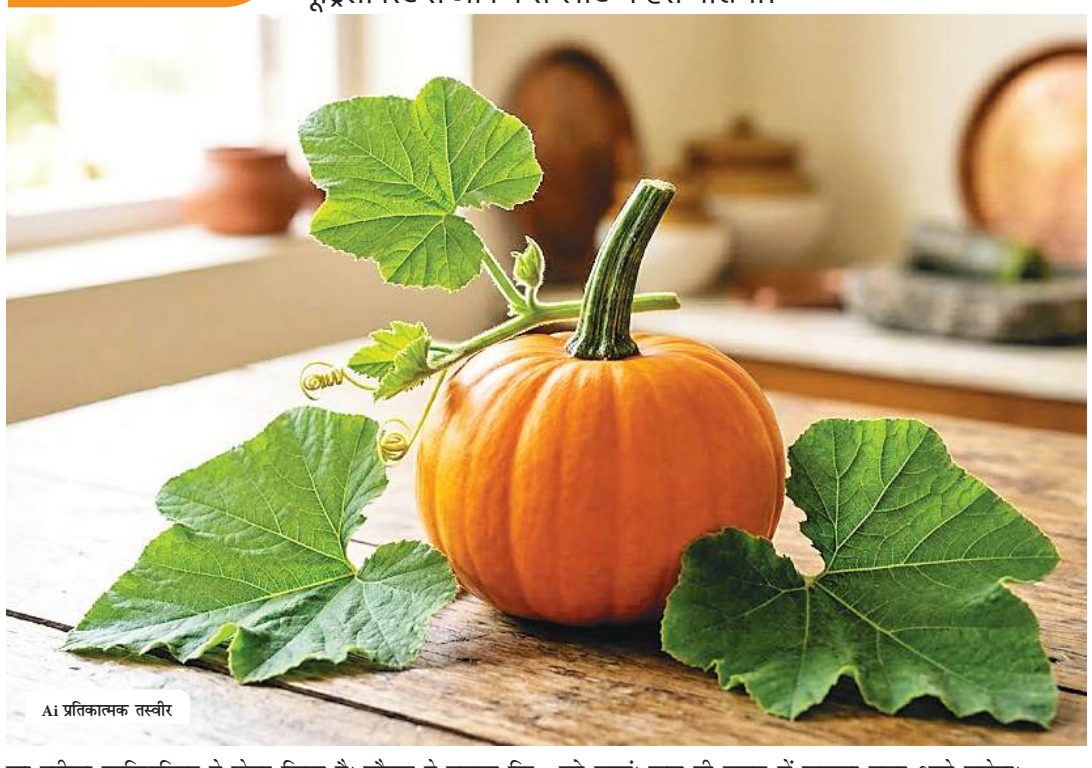

Ai प्रतिकात्मक तस्वीर

काफी सारी महिलाओं को हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है। बालों का झड़ना, स्किन का फीका दिखना बिल्कुल कॉमन समस्या है। दरअसल, महिलाओं में आयरन की कमी ज्यादातर रहती है। जिससे निपटने के लिए वो कई तरह के मेडिसिन और फूड्स खाती हैं। लेकिन एक पत्ती है जो इन समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या गिरीश राव ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है और बताया है कि कैसे कद्दू की पत्तियों से आयरन की कमी को दूर किया जा सकता है।

पंपकिन लीफ से दूर होगी आयरन की समस्या : आयरन की कमी से महिलाओं में थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, डार्क सर्कल, शरीर में दर्द की समस्या होती है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कद्दू की पत्तियां मदद कर सकती हैं। इन पत्तियों को खाने से इतने सारे फायदे होंगे

खून बढ़ेगा : पंपकिन लीफ में आयरन और फोलेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जिससे से ये आयरन की समस्या से लड़ने में मदद करता है। ये रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को तेज करने में मदद करता है। जिससे शरीर की थकान और कमजोरी कम होती है।

इम्यून सिस्टम मजबूत होगा : कद्दू की पत्तियों में विटामिन सी की मात्रा भी अच्छी खासी होती है। जिससे ये शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ाते हैं जो किसी भी तरह के इंफेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं।

हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करता है : पंपकिन लीफ में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है। जो हड्डियों और जोड़ों की हेल्थ को मेंटेन करता है। महिलाएं अगर इसे लगातार खाएं तो ऑस्टियो पोरोसिस की समस्या होने से बचत होती है।

स्किन को यंग बनाता है : विटामिन ए और सी कोलेजन का प्रोडक्शन करते हैं। इन पत्तियों में दोनों की ही मात्रा अच्छी खासी होती है। जिससे ये स्किन इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है। और अल्ट्रा वॉयलेट रेज से होने वाले डैमेज को रिपेयर करता है।

डाइजेस्टिव हेल्थ : पंपकिन लीफ में फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है जो डाइजेशन को इंप्रूव करता है और बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है।

कैसे खाएं कद्दू की पत्तियां : कद्दू की पत्तियों को खाने का तरीका न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया है। सौम्या ने बताया कि कद्दू की ताजी, हरी और कोमल नई पत्तियों को लेकर घी में रोस्ट कर लें और फिर इसे चना, उड़द या फिर पंपकिन सीड्स के साथ मिलाकर चटनी पीस लें। सप्ताह में तीन दिन इस चटनी को खाएं। कुछ ही समय में फायदा नजर आने लगेगा।

डिस्क्लेमर : इस लेख के सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें।

मोदी की व्यापार दृष्टि ने भारत को बदलने के लिए विश्व-स्तर पर अवसरों के द्वार खोले

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

यूके के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौता, जो 15 जुलाई से लागू होगा, भारतीय किसानों, एमएसएमई, मछुआरों, स्टार्टअप और कारीगरों के लिए वैश्विक अवसर और समृद्धि लाएगा। यह नौकरियां सृजित करेगा और भारतीय नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सामान को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराएगा, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 मिशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारत और यूके के बीच परिवर्तनकारी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) भारतीय वस्तुओं के लिए यूके में सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, व्यापक बाजार पहुंच सुनिश्चित करेगा। दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद यह समझौता लगभग 100% व्यापार मूल्य को शामिल करते हुए लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर तुरंत शुल्क समाप्त करेगा, जिससे भारतीय निर्यात के लिए अपार अवसर सृजित होंगे।

सीईटीए एक जन-केंद्रित समझौता है, जिस पर पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये थे। यह समाज के हर हिस्से को फायदे देता है। किसानों को अपने घरेलू हितों से समझौता किए बिना उच्च मूल्य वाले निर्यात बाजारों तक पहुंच मिलेगी। मछुआरों को विशाल यूके बाजार में अधिक सीफ़ूड निर्यात से फायदा मिलेगा। श्रमिकों को श्रम-गहन क्षेत्रों में नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। महिला उद्यमी, युवा, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को वैश्विक मूल्य-श्रृंखला तक बेहतर पहुँच मिलेगी। पेशेवरों को बेहतर आवागमन और मान्यता के अवसरों से फायदा मिलेगा।

किसानों के लिए समृद्धि : सीईटीए भारतीय किसानों के लिए प्रीमियम यूके बाजार खोलता है, जो दूसरे यूरोपीय देशों को मिलने वाले फायदों के बराबर या उनसे भी बेहतर है। हल्दी, काली मिर्च, इलायची और प्रसंस्कृत सामान जैसे आम का गूदा, अचार और दालों को शुल्क -मुक्त पहुँच प्राप्त होगा। उच्च कृषि निर्यात से किसानों की आय बढ़ेगी और गुणवत्ता, पैकेजिग और प्रमाणन के लिए और प्रोत्साहन मिलेगा। यह कृषि मूल्य श्रृंखला में कई नौकरियाँ भी पैदा करेगा।

साथ ही, सीईटीए घरेलू किसानों - खासकर डेयरी उत्पाद, खाद्यान्न, मोटे अनाज, सेब, ओट्स और खाद्य तेल से जुड़े किसानों - की सुरक्षा के लिए भारत के सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को अपने दायरे से बाहर रखता है। इन्हें समझौते से बाहर रखना, मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा, घरेलू मूल्य स्थिरता और कमजोर कृषि समुदायों को प्राथमिकता देने की रणनीति को प्रतिबिंबित करती है।

उद्योग को बढ़ावा : यूके के विशाल बाजार तक तुरंत शुल्क-मुक्त पहुंच भारतीय निर्माण को बढ़ावा देगी, जिससे पारंपरिक कारीगर, बड़े कारखाने और क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्र प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। छोटे व्यवसायों को फायदा होगा, क्योंकि भारतीय उत्पादों को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर प्रतिस्पर्धा से जुड़ी स्पष्ट बढ़त मिलेगी। फुटबॉल, क्रिकेट गियर, रग्बी बॉल और खिलौने बनाने वाली कंपनियां, अन्य उत्पादों के साथ-साथ, यूके में अपने व्यवसाय को काफी विस्तार देने में सक्षम होंगी।

पीयूष गोयल
(लेखक केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।)

शुल्कों को हटाने से खासकर श्रम-सघन क्षेत्रों में लंबे समय से चल रही टैरिफ बाधाओं का समाधान हुआ है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धा और पैमाने में तुरंत लाभ होने की उम्मीद है। तिरुपुर के करघों से लेकर बेंगलुरु की लैब तक, सूरत के हीरे के कारीगरों से लेकर हैदराबाद के कोडर्स तक, यह समझौता असली अर्थव्यवस्था को छूता है।

सेवाएँ और पेशेवर : यूके ने सेवा क्षेत्र में अब तक की अपनी सबसे व्यापक प्रतिबद्धताओं में से एक प्रदान किया है, जिसमें भारत की निर्यात रुचि के सभी प्रमुख सेवा क्षेत्रों और 137 उप-क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बेहतर बाजार पहुंच और नियामक सुनिश्चितता भारतीय सेवा प्रदाताओं को आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, पेशेवर सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श सेवाओं में सहायता करेगी। भारत ने कुशल पेशेवरों के लिए अनुकूल आवागमन प्रावधान सुनिश्चित किए हैं, जिनमें संविदा सेवा प्रदाता, व्यापार यात्री, निवेशक, योग प्रशिक्षक, संगीताकार और रसोइये शामिल हैं। इस समझौते में व्यापार आगंतुक, कर्मचारियों का अंतर-कॉर्पोरेट तबादला, संविदा सेवा आपूर्तिकर्ता, स्वतंत्र पेशेवर और निवेशकों के लिए भी पूर्वानुमान योग्य आवागमन उपाय प्रदान किए गए हैं।

इसके अलावा, इस समझौते के तहत 1,800 भारतीय रसोइये, योग प्रशिक्षक और शास्त्रीय संगीतकार हर साल समर्पित आवागमन अवसरों का लाभ उठा सकेंगे।

नवोन्मेषी एफटीए : पीएम मोदी के नेतृत्व में, एफटीए सिर्फ वस्तुएं और सेवाओं तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्होने नए मानक स्थापित किये हैं। ईएफटीए देशों—स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन—के साथ, भारत ने 100 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार के एक मिलियन अवसरों के सृजन की उम्मीद है। न्यूज़ीलैंड के साथ एफटीए में, देश ने 15 साल में 20 बिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की, जबकि ऑस्ट्रेलियाई एफटीए ने उस दोहरी कर-व्यवस्था की समस्या को सुलझा दिया, जिससे भारतीय आईटी कंपनियां समस्याओं का सामना करती थीं। यूके के साथ समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू है, दोहरा योगदान सिद्धांत। यह ऐतिहासिक व्यवस्था, जो सीईटीए के साथ प्रभावी होगी, भारतीय कर्मचारियों और नियोक्ताओं को अस्थायी कार्य-उत्तरदायित्व (असाइनमेंट) के दौरान यूके में दोहरी सामाजिक सुरक्षा योगदान देने से मुक्त करती है।

75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से अधिक कंपनियों को अस्थायी विदेशी कार्य-उत्तरदायित्व पर कर्मचारियों के लिए लगातार सामाजिक सुरक्षा कवरेज से फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार की रणनीति : 2014 में अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही थी और संभावित निवेशकों का भरोसा टूट रहा था। भारत को उन "कमजोर पांच" अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता था, जो नीतिगत भटकाव और भारी भ्रष्टाचार घोटालों से जूझ रही थीं।

मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक विश्वास बहाल करने और इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए एक सुदृढ़ दृष्टिकोण अपनाया। विकसित देशों के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर करना अगला कदम था। एफटीए व्यापार नीतियों के संबंध में अनिश्चितता को कम करके निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाते हैं।

सरकार ने ऐसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ एफटीए किये, जो बड़े बाजार प्रदान करती हैं और भारत के प्रमुख व्यापार हितों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करतीं। इससे दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद स्थिति बनती है, जो पिछली सरकार के उस दृष्टिकोण से अलग है, जिसमें भारतीय व्यवसायों को जोखिम में डालते हुए देश के दरवाजे प्रतिद्वंद्वियों के लिए लापरवाही से खोल दिए गए थे।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत को अब एक मजबूत अर्थव्यवस्था और अस्थिर विश्व में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। इसने खुद को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित किया है, जिसका एक आकर्षक बाजार है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। महत्वपूर्ण और व्यापक सुधारों, व्यवसाय करने में आसानी में सुधार, छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने और पीएम के वैश्विक व्यक्तित्व ने भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। आज, दुनिया भारत की विकास कहानी का हिस्सा बनना चाहती है—और एफटीए पर हस्ताक्षर करना चाहती है।

इन व्यापार समझौतों ने घरेलू बाजार को भी धीरे-धीरे खोलना सुनिश्चित किया है। इससे भारतीय बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी होगा और स्थानीय निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले सामान प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जो प्रधानमंत्री के विकसित भारत मिशन का एक मुख्य तत्व है।

भारत की नई कृषि यात्रा : फसल से आगे, समृद्धि की ओर

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारतीय कृषि एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि देश में अनाज की कमी न हो, किसी तरह भूख से बचाव हो जाए। आज मोदी जी की दूरदर्शिता और किसान-हितैषी नीतियों ने कृषि को सिर्फ "उत्पादन का क्षेत्र" नहीं रहने दिया, बल्कि किसान की समृद्धि, जोखिम-सुरक्षा, पोषण सुरक्षा, हरित तकनीक और ग्रामीण विकास का समन्वित आधार बना दिया है। हरित क्रांति के बाद पहली बार नीतियों का फोकस केवल "कितना उत्पादन" पर नहीं, बल्कि "किसान की वास्तविक आय कितनी, खेती कितनी टिकाऊ, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितनी मज़बूत" पर आ गया है। इसी सोच से दलहन-तिलहन मिशन, कॉटन मिशन, प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, खेत बचाओ अभियान, डिजिटल कृषि और शोध-नवाचार; सबको एक ही व्यापक दृष्टि से जोड़ा जा रहा है।

उत्पादन से आगे : आय, सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था – आज भारत खाद्यान्न उत्पादन में 3765.63 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर है, जो देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। धान, गेहूँ, मक्का, दालें और तिलहन- सभी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। यह केवल ज्यादा पैदावार नहीं, बल्कि कुल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए विस्तार और मजबूती का प्रमाण है। साथ-साथ, मोदी सरकार ने किसान की जोखिम-सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत अब तक 22 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे 4.27 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता पहुँच चुकी है, जिससे 9 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को हर साल नियमित आय-समर्थन मिलता है। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) ने देशभर में करोड़ों किसान-आवेदनों को कवर करते हुए फसल के नुकसान की स्थिति में एक मज़बूत बीमा कवच दिया है। सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, कृषि-अवसंरचना, वेयरहाउस और कोल्ड-चेन में निवेश ने उत्पादन, भंडारण और बाज़ार तक पहुँच- तीनों को मजबूत किया है। कृषि अब सिर्फ खेत की मेड़ तक सीमित नहीं है। डेयरी, मत्स्य, कुक्कुट, बागवानी, मधुमक्खी-पालन, खाद्य-प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रामीण उद्योग, सौर ऊर्जा और सेवा-क्षेत्र; सब मिलकर नई ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

शिवराज सिंह चौहान
(लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं।)

दलहन, तिलहन और कॉटन मिशन : आत्मनिर्भरता और मूल्य-सुरक्षा – लंबे समय तक दालें, खाद्य तेल और कपास- तीनों क्षेत्र हमारी पूरी क्षमता से पीछे रहे। हम दालों और तेलों के लिए आयात पर निर्भर रहे और कपास में भी किसानों को वैश्विक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार ने इन तीनों को रणनीतिक प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग मिशन के रूप में आगे बढ़ाया है। राष्ट्रीय दलहन मिशन के माध्यम से तुअर, उड़द, मसूर, चना और अन्य दालों का क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाज़ार तक पूरी वैल्यू चेन पर काम हो रहा है- उच्च-उपज किस्में, क्लस्टर आधारित खेती, प्रसंस्करण इकाइयाँ, MSP का सुदृढ़ ढाँचा, सरकारी खरीद, भंडारण और निर्यात तक। लक्ष्य यह है कि भारत दालों में पूरी तरह आत्मनिर्भर बने, आयात बिल घटे और किसानों को उच्च मूल्य वाली इन फसलों से स्थायी आय मिले। इसी तरह तिलहन मिशन के ज़रिए सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल और पाम ऑयल जैसी फसलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह केवल पैदावार बढ़ाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता, किसानों को बेहतर दाम और देश की तेल सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में व्यापक रणनीति है। इसके साथ-साथ कॉटन मिशन के तहत कपास की उच्च-उपज और कीट-रोधी किस्में, उन्नत कृषि-प्रणालियाँ, कीट-प्रबंधन, फसल विविधीकरण, टेक्सटाइल वैल्यू-चेन से बेहतर जुड़ाव और गुणवत्ता सुधार पर काम हो रहा है। कपास भारत के लाखों किसानों के लिए नकदी फसल है; मिशन का उद्देश्य है कि किसान को उत्पादन के साथ-साथ वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा योग्य गुणवत्ता, बेहतर मूल्य और स्थिर आय भी मिल सके।

प्राकृतिक खेती मिशन : 1 करोड़ किसान, 75 लाख हेक्टेयर की नई राह – तेज़ी से बढ़ती रासायनिक निर्भरता, मिट्टी की थकान और भूजल पर दबाव- ये सब हमें आगाह कर रहे हैं कि खेती के तरीके बदलने होंगे। इसी समझ के साथ हमारे विजनरी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सेंसिटाइज़ किया जाए, उनमें से लगभग 18 लाख किसानों को सक्रिय रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए तैयार किया जाए और चरणबद्ध रूप से करीब 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाए।

यह परिवर्तन धीरे-धीरे, वैज्ञानिक प्रमाणों और किसानों के अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ रहा है। छोटे किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपनी कुछ भूमि पर प्राकृतिक खेती का मॉडल बनाकर देखें; उन्हें प्रशिक्षण, स्थानीय संसाधनों पर आधारित पैकेज, प्रमाणन, ब्रांडिंग और बाज़ार-जुड़ाव में मदद दी जा रही है। उद्देश्य यह है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़े, रासायनिक लागत घटे, जलवायु झटकों के सामने फसलें अधिक टिकाऊ हों और उपभोक्ताओं को स्वास्थ्यप्रद, पोषक भोजन मिल सके।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और फोकस में 100 कम उत्पादन वाले ज़िले – भारत जैसे विशाल देश में कुछ क्षेत्र बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ ज़िले अलग-अलग वजहों से पीछे रह जाते हैं। इस असमानता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत लगभग 100 कम उत्पादन वाले ज़िलों की पहचान की गई है, जहाँ प्रति हेक्टेयर पैदावार राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और किसान अपेक्षित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इन ज़िलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं का कन्वर्जेन्स कर एक समग्र पैकेज दिया जा रहा है- सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, बीज, उर्वरक, फसल विविधीकरण, पशुपालन, बागवानी, कृषि-उपकरण, कौशल विकास, अवसंरचना और बाज़ार-जुड़ाव; सबको एक साथ जोड़कर। सोच यह है कि योजनाएँ अलग-अलग "साइलो" में न चलें, बल्कि किसान के खेत और गाँव को केंद्र में रखकर सब मिलकर काम करें।

नया आधार ऐप : 5 महीने में 31 मिलियन डाउनलोड, जीवन हुआ सुगम

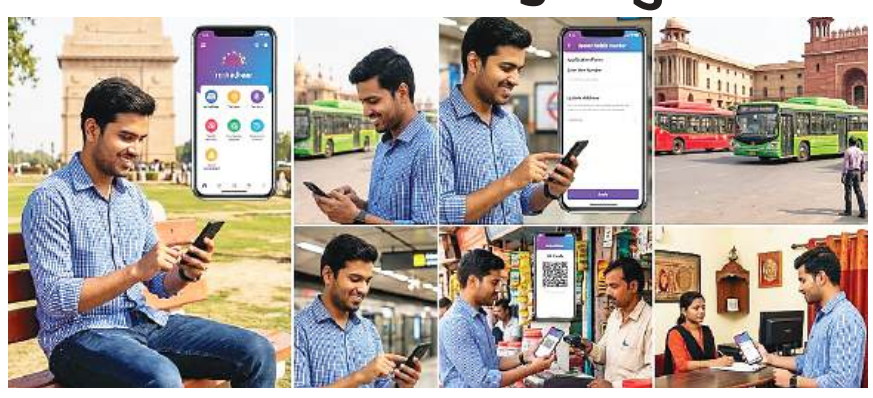

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

आधार ऐप को भारत भर में लोगों के बीच अत्यधिक स्वीकृति मिल रही है। लॉन्च होने के 5 महीने से भी कम समय में इसे 31 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। बढ़ती लोकप्रियता ऐप पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है, क्योंकि यह लोगों को उनकी उंगलियों पर ही सेवाएं उपलब्ध कराता है।

जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया नया आधार ऐप लोगों को अपने स्मार्टफ़ोन से ही मोबाइल नंबर अपडेट और पता अपडेट सहित विभिन्न सेवाओं का सुगमता से लाभ उठाने में सक्षम बना रहा है।

अब तक लगभग चार मिलियन लोगों ने नए आधार ऐप का उपयोग करके अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं। वहीं, लगभग 8,50,000 लोगों ने ऐप का उपयोग करके अपना पता अपडेट किया है।

आधार ऐप को आधार नंबर धारकों (एएनएच) को अपनी पहचान दिखाने, साझा करने और सत्यापित करने का एक सुविधाजनक और गोपनीयता-प्रथम तरीका प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस ऐप में कई जनहितकारी सुविधाएं हैं, जिनमें एक क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, उपस्थिति प्रमाण के लिए चेहरे का सत्यापन, प्रमाणीकरण इतिहास और वास्तविक विज़िटिंग कार्ड के बजाय संपर्क जानकारी साझा करने के लिए क्यूआर-कोड आधारित संपादन योग्य संपर्क कार्ड शामिल हैं। यह ई-आधार डाउनलोड करने की सुविधा भी देता है और आधार सेवा केंद्रों (एएसके) आदि पर जाने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना सरल बनाता है।

आधार ऐप कई तरह के वास्तविक जीवन के उपयोगों में सहायता करता है। इनमें ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (ओवीएससई) के क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से होटल चेक-इन शामिल है। यह अस्पताल में भर्ती, आगंतुक प्रबंधन, इवेंट एंट्री, गिग वर्कर्स और सर्विस पार्टनर्स की पहचान सत्यापन जैसे कई अन्य उपयोगों में भी सहायक है।

नया आधार ऐप एंड्रॉयड और ऐप्पल आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लोग इसे यहां से डाउनलोड कर सकते हैं:

एंड्रॉइड: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.pehchaan&hl=en_IN

आईओएस - https://apps.apple.com/in/app/aadhaar/id6744029871

जल शक्ति : विकसित भारत की यात्रा को दे रही है गति

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

क्या आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम है? या फिर स्वच्छ भारत मिशन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता अभियान है, जिसने लोगों की सोच और व्यवहार में अभूतपूर्व बदलाव लाया है? और क्या आपको पता है कि नमामि गंगे आज दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी नदी पुनर्जीवन योजनाओं में शामिल है? ये सभी पहल केवल सरकारी योजनाएं नहीं हैं, बल्कि इस बात का उदाहरण हैं कि 145 करोड़ आबादी वाला भारत किस तरह पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

सी. आर. पाटिल
(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं।)

जब इतिहासकार भारत की विकास यात्रा को देखेंगे, तो संभव है कि वे पिछले 12 वर्षों को वह दौर बताएं, जब 'जल' देश के विकास का सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया। मानव सम्मान, आर्थिक विकास, जनस्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण संरक्षण पर पानी जितना प्रभाव डालता है, उतना शायद ही कोई दूसरा क्षेत्र डालता हो। लेकिन कई दशकों तक भारत में जल संबंधी समस्याओं का समाधान अलग-अलग और बिखरे हुए तरीकों से किया जाता रहा। पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए एकीकृत, गंभीर और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पिछले 12 वर्षों में जल क्षेत्र में जितने बड़े पैमाने पर निवेश और काम हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इस बदलाव की अहमियत केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है। आज पानी को पूरे देश की साझा प्राथमिकता माना जा रहा है, जिसमें सभी विभाग, राज्य, समुदाय और आने वाली पीढ़ियाँ भागीदार हैं। पहले जल क्षेत्र को उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जल क्षेत्र की योजना, प्रबंधन और सेवाओं से जुड़ी वर्षों पुरानी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई।

इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण जल जीवन मिशन है। जब यह मिशन शुरू हुआ था, तब केवल लगभग 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों, यानी करीब 17 प्रतिशत ग्रामीण घरों में ही नल से जल की सुविधा थी। आज 15.8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों, यानी 81 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से पानी पहुँच चुका है। सरकार का लक्ष्य 2028 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध कराना है। लाखों परिवारों, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए यह केवल पानी की सुविधा नहीं है, बल्कि उनके जीवन में आया एक बड़ा बदलाव है।

अध्ययनों के अनुसार, पहले भारत की ग्रामीण महिलाओं को हर साल पानी लाने में अरबों घंटे खर्च करने पड़ते थे। अब घर-घर नल से पानी पहुंचने के कारण हर दिन 5.5 करोड़ से अधिक व्यक्ति-घंटों की बचत हो रही है। जो समय पहले पानी लाने में लगता था, अब उसका उपयोग पढ़ाई, रोजगार, बच्चों की देखभाल और आय बढ़ाने वाले कामों में हो रहा है।

रिफॉर्म एक्स प्रेस के अंतर्गत बढ़ रही न्यायिक सुगमता

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

न्याय सदा से ही मानव सभ्यता का एक अत्यशधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न स्तंभ रहा है। हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की समृद्ध परंपरा तथा उसके स्थायी प्रतीक सामूहिक रूप से उन संस्थागत व्यसवस्था ओं को दर्शाते हैं जिन्होंने मानव सभ्यरता की विकास यात्रा को सही मार्ग पर आगे बढ़ाया, मार्गदर्शन किया और निरंतर आगे बढ़ने में सहायता की।

अर्जुन राम मेघवाल
(लेखक भारत सरकार में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं)

मानव सभ्यतता के अनवरत विकास के फलस्वंरूप ज्ञान-विज्ञान और तकनीक से समृद्ध आधुनिक समाज में एक-दूसरे से जुड़े व्य क्तियों और समुदायों के आपसी संबंधों में भी विभिन्न विचारों और मतों के कारण परिवर्तन आया है, तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी उन्नपति ने देश की सीमाओं से आगे जाकर विचारों के निर्बाध आदान-प्रदान को और अधिक सुगम बनाया है।

अनादि काल से, एक विचार की दूसरे विचार पर श्रेष्ठता स्थाापित करने की होड़ न्यायशास्त्र के विकास की एक मजबूत नींव रही है। युगों से विचारों और मूल्यों के इस अंतर्संघर्ष के बीच न्यायिक संस्थानों ने सत्य, निष्पक्षता और विधि के शासन में लोगों के विश्वास को पुन: स्थायपित करने की जिम्मेनदारी निभाई है। इन्होंने एक सेतु का काम किया है जो प्रत्येक संबंधित पक्ष को, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो स्वयं को अलग-थलग महसूस करते हैं, न्याय और सामूहिक कल्या ण की एक व्यापक प्रक्रिया से जुड़ाव, विश्वा्स और सहभागिता का अनुभव कराता है।

इसी स्था यी संस्थालगत प्रतिबद्धता के कारण एक ऐसी सशक्त व्यवस्था निर्मित होती है जो न केवल न्यीय तक पहुंच सुनिश्चित करती है बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए अनिवार्य है। वर्तमान संदर्भ में विकसित भारतीय न्यायशास्त्रे ने स्वनयं को आधुनिक चुनौतियों और उपलब्धन अवसरों के अनुरूप ढाल लिया है। हमारी संवैधानिक विरासत हमें स्व तंत्रता सेनानियों और राष्ट्रो निर्माताओं का स्वाप्नं साकार करते हुए एक समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में सतत मार्गदर्शन प्रदान करती है। संविधान की प्रस्ताहवना में निहित न्यायि की त्रिवेणी अर्थात राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा स्वातंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श संस्था,ओं और व्यआक्तियों दोनों के लिए एक नैतिक दिशासूचक के रूप में कार्य करते हैं।

स्वतंत्र भारत को संविधान के रूप में एक आदर्श मार्गदर्शक प्राप्त हुआ जिसने हमारे राष्ट्रत की प्रग ति की दिशा निर्धारित की। देश की आजादी के बाद यद्यपि हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, फिर भी गहरी जड़ें जमा चुकी औपनिवेशिक मानसिकता भारतीय चिंतन और मूल्यों के लिए एक बौद्धिक अवरोध बनी रही। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, उसके बाद भारत के नागरिकों के लिए बनाए गए दंडात्मक कानून तथा विभिन्नर नीतियों ने नियमों का एक जटिल जाल बुन दिया, जिसने देश की जनता की स्वतंत्रता को सीमित किया। 19वीं सदी की मानसिकता और 20वीं सदी के कानून 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते।

मोदी के कार्यकाल के बारह वर्षों ने समूची दुनिया को भारत को अलग

• **जालंधर ब्रीज** . नई दिल्ली

उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत बेहतरीन संकट-प्रबंधक के रूप में प्रमाणित किया है। केवल उनके दृढ़ संकल्प, साहस और सावधानीपूर्वक की गई कार्रवाई के बल पर ही 1.4 बिलियन भारतीयों का महामारी जैसी सदी की भीषणतम आपदा से सुरक्षित निकालना तथा उस आपदा को अवसर में बदलना संभव हुआ। वह अब भारत का नेतृत्व ऐसे समय में कर रहे हैं, जब वैश्विक भूराजनीतिक और भू-आर्थिक व्यवस्था खतरनाक उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है।

लक्ष्मी पुरी
(लेखिका संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव और यूएन विमेन की पूर्व उप कार्यकारी निदेशक हैं)

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। यह उपलब्धि उनकी भी है और भारत की भी: उनसे पहले किसी ने भी इस लोकतंत्र में लगातार इतने लंबे समय तक शासन नहीं किया और न ही इतनी प्रतिस्पर्धी राजनीति के बीच किसी ने लगातार तीन बार चुनावी जीत हासिल की है। हालाँकि, रिकॉर्ड से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने क्याग कार्य किया है : अपने कार्यकाल के "प्रत्ये क मिनट" के पूरे "साठ सेकेंड का भारत के लिए पूरी ऊर्जा के साथ उपयोग करते हुए उसे सार्थक बनाया", उनके इन बारह वर्षों का प्रत्येकक वर्ष 365 दिनों की उपलब्धियों से चिह्नित रहा, और इसी दौरान उस नए, गतिशील भारत का निर्माण हुआ, जिसे आज दुनिया एक अलग नजरिए से देख और समझ रही है। मैंने अपनी कामकाजी ज़िंदगी फील्ड में, राजधानियों में, बोर्ड और कॉन्फ्रेंस रूम में तथा संयुक्त राष्ट्र में बितायी है—जहाँ देशों के बारे में दुनिया अपनी राय कायम करती है। बीते एक दशक जो परिवर्तन आया है, वह मेरे द्वारा देखे गए परिवर्तनों में सबसे अधिक उल्लेखनीय है: भारत के प्रति पहले जो उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण हुआ करता था, उसकी जगह अब प्रतिस्पर्धी रुचि, सीखने की इच्छा ने ले ली है, दुनिया भारत के उस परिवर्तन को विस्मय से देख रही है, जिसमें वह एक 'सिद्धांतों के आधार पर आपत्ति दर्ज करने वाले' और 'व्यवस्था को स्वीकार करने वाले' देश की जगह अब 'व्यवस्था को आकार देने वाले' देश के रूप में उभरा है, आज भारत बहुआयामी कूटनीतिक सहभागिता और रणनीतिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। वह न केवल अपने प्रभाव का उपयोग अपने विचारों के समर्थन में कर रहा है, बल्कि अपने विचारों के समर्थन को भी शक्ति में परिवर्तित कर रहा है।

दुनिया इस शख्सियत का सही आकलन करती है: उन्हें सत्ता विरासत में नहीं मिली; उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सर्वोच्च पद तक का सफर बिना किसी पारिवारिक नाम के सहारे, रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर बीते बचपन से तय किया; उन्होंने भारत के कोने-कोने की यात्रा की, लोगों को समझा, उनके साथ बैठकर भोजन किया, उनके सुख-दुःख में भागीदार बने और जमीनी स्तर से अपना राजनीतिक जीवन निर्मित किया। वंशानुगत सत्ता और विशेषाधिकार प्राप्त उत्तराधिकार से ऊब चुकी दुनिया में, ऐसे नेता की छवि अधिक भरोसेमंद होती है, जिन्होंने अपनी पहचान स्वयं गढ़ी हो।

एसआईआर-2026 : पंजाब भर में घर-घर गणना शुरू

24,453 बीएलओज़ ने घर-घर जाकर फॉर्म वितरित किए

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

प्रदेश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के तहत गुरुवार को 24,453 बीएलओज़ ने घर-घर दौरे शुरू कर दिए हैं। भारत चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित गणना चरण 25 जून से 24 जुलाई, 2026 तक जारी रहेगा, जिसके तहत पंजाब भर के 2,14,61,043 मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाएगी। घर-घर गणना के पहले दिन प्रदेश के लोगों के लिए बेहतरीन उदाहरण पेश करते हुए अनिंदिता मित्रा, आईएएस, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब ने अपने परिवार सहित अपना गणना फॉर्म भरा और सही, समावेशी तथा संशोधित मतदाता सूची तैयार करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे गणना फॉर्म वितरित करने और भरने में सहायता के लिए अपने घरों का दौरा करने वाले बी.एल.ओज़. का सहयोग करें। श्रीमती मित्रा ने बताया कि पहला दिन बहुत उत्साहजनक एवं सकारात्मक रहा, प्रदेश में गणना फॉर्म पूरी सफलता से वितरित किए गए। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपनी एक ताज़ा रंगीन फोटो तैयार रखें, फॉर्म भरकर, उस पर हस्ताक्षर करें और बी.एल.ओ. को सौंप दें तथा विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) प्रक्रिया पूरी होने तक दूसरी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। सी.ई.ओ. ने मतदाताओं को विश्वास दिलाते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई घर बंद पाया जाता है तो बी.एल.ओ. फॉर्म को दरवाजे के नीचे से अंदर पहुंचा देगा और संबंधित घर के अगले दौरे की तारीख के बारे में दीवार पर स्टिकर चिपका दिया जाएगा। बी.एल.ओ. फॉर्म एकत्र करने के लिए तीन बार घर-घर जाएंगे। यदि मतदाता घर पर उपस्थित नहीं है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, संबंधित व्यक्ति से अपना रिश्ता बताकर उसके फॉर्म पर हस्ताक्षर करके फॉर्म वापस बी.एल.ओ. को दे सकता है।

उन्होंने कहा कि सहायता के लिए मतदाता ईसीआईनेट मोबाइल ऐप का उपयोग भी कर सकते हैं। मतदाता ईसीआईनेट मोबाइल ऐप या मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी भरा हुआ गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं, जिसका सत्यापन संबंधित बी.एल.ओ. द्वारा किया जाता है। पिछले एस.आई.आर. रिकॉर्ड तक भी इन प्लेटफार्मों के माध्यम से पहुंच बनाई जा सकती है। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तीकरण (रैशनलाइजेशन) की प्रक्रिया 24 जुलाई, 2026 तक जारी रहेगी, जबकि मसौदा मतदाता सूचियाँ 3 अगस्त, 2026 को प्रकाशित की जाएंगी। मतदाता सूचियों से संबंधित दावे और आपत्तियाँ 3 अगस्त से 2 सितंबर, 2026 तक जमा करवाई जा सकती हैं, जिनका निपटान 3 अगस्त से 28 सितंबर, 2026 तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जोर देकर कहा कि पंजाब में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है ताकि सही एवं संशोधित मतदाता सूचियाँ सुनिश्चित की जा सकें।

डिप्टी कमिश्नर ने जालंधर में चल रहे घर-घर सर्वेक्षण का लिया जायजा, विभिन्न इलाकों का किया दौरा

जालंधर (जालंधर ब्रीज). डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी वरजीत वालिया ने मतदाता सूचियों की चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर)-2026 के तहत शुरू हुए एक माह चलने वाले घर-घर सर्वेक्षण का जायजा लेने के लिए विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम जालंधर-1 शुभी आंगरा भी मौजूद थीं। अपने दौरे के दौरान स्थानीय निवासियों से बातचीत करते हुए वालिया ने उन्हें एसआईआर के उद्देश्य और प्रक्रिया से परिचित करवाया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों को सही, पारदर्शी और अपडेट बनाना है। उन्होंने मतदाताओं को बताया कि बी.एल.ओ. द्वारा पहले से छपे हुए गणना फॉर्म दिए जाएंगे, जिन्हें भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि फॉर्म पर हस्ताक्षर की गई एक कॉपी बीएलओ द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी, जबकि दूसरी कॉपी पर बीएलओ के हस्ताक्षर होंगे और मतदाता उसे रसीद के रूप में रख सकेंगे। फॉर्म को मतदाता या घर के किसी भी बालिग सदस्य द्वारा भरा और जमा किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी घर पर ताला लगा होगा या मतदाता घर पर उपलब्ध नहीं होंगे तो बीएलओ. उस घर पर कम से कम तीन बार दौरा करेंगे।

कपूरथला में बीएलओ ने पहले दिन 63,652 गणना फॉर्म वितरित किए

कपूरथला (जालंधर ब्रीज). चुनाव आयोग के निर्देशों पर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की शुरुआत हुई, जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर अभियान के पहले दिन 63652 गणना फॉर्म वितरित किए। डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी अकाश बांसल ने बताया कि गुरुवार को जिले भर में घर-घर अभियान शुरू किया गया और कुल 791 बीएलओ चार विधानसभा क्षेत्रों में 6,14,981 मतदाताओं तक पहुंचेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे चल रहे एसआईआर अभियान में सक्रिय भागीदार बनें ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। उन्होंने कहा कि बी.एल.ओ. से फॉर्म प्राप्त करने के बाद मतदाताओं को उसे भरकर रखना होगा और जब बीएलओ दोबारा फॉर्म एकत्र करने आएगा, तब उसे वापस सौंपना होगा। साथ ही उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक बी.एल.ओ. लगभग 750 से 842 मतदाताओं के लिए जिम्मेदार होगा और पहले दिन शाम 6 बजे तक घर-घर दौरे के दौरान 63652 फॉर्म वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बीएलओ हर घर में अधिकतम तीन बार जाएगा। यदि कोई घर बंद मिलता है तो गणना फॉर्म दरवाजे पर छोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को पहले से छपे फॉर्म की दो कॉपी दी जाएंगी—एक मूल और एक डुप्लीकेट। मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे मूल फॉर्म भरकर बीएलओ की अगली फेरी के दौरान उसे सौंप दें। फॉर्म प्राप्त करने के बाद बीएलओ रसीद जारी करेगा।

40 दिनों का 'छात्रों की गूंज' अभियान, देश के हर कोने तक पहुंचेगा : राजीव शुक्ला

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

कांग्रेस ने देश में बार-बार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ियों और बढ़ती बेरोज़गारी के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने देशभर में 'छात्रों की गूंज' नाम से 40 दिनों का अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं, बार-बार परीक्षा रद्द होने और देरी के खिलाफ छात्रों को एकजुट करना है। साथ ही कांग्रेस ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पूरे परीक्षा तंत्र में बड़े सुधार की मांग की है। इस अभियान की घोषणा करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीडब्ल्यूसी सदस्य राजीव शुक्ला, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष हरमोहिंदर लक्की और एआईसीसी कॉर्डिनेटर हुसैन सुल्तानिया ने बताया कि यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। इसके तहत कोचिंग सेंटर, विश्वविद्यालय, छात्रावास, लाइब्रेरी और सार्वजनिक स्थानों पर छात्रों से संवाद किया जाएगा।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बार-बार होने वाले पेपर लीक और परीक्षा विवादों ने छात्रों का भरोसा पूरी तरह हिला दिया है। यह अब सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों और नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का राष्ट्रीय संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य मुद्दा नीट यूजी 2026 परीक्षा है। आरोपों के बाद 3 मई को हुई परीक्षा रद्द करनी पड़ी, सीबीआई जांच शुरू हुई और 20 लाख से अधिक छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। इससे छात्रों को भारी मानसिक और शैक्षणिक नुकसान हुआ।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने का मामला नहीं है, बल्कि उन संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा टूटने का मामला है, जिनकी जिम्मेदारी निष्पक्ष परीक्षा करवाने की है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान हुई गिरफ्तारियां दिखाती हैं कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियां हैं। अगर प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले लीक हो सकते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ छोटे कर्मचारियों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की तय होनी चाहिए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह लगातार हो रहे पेपर लीक रोकने में पूरी तरह विफल रही है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। नेताओं ने कहा कि परीक्षा में लगातार हो रही गड़बड़ियों का असर केवल छात्रों पर ही नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं पर भी पड़ा है जो सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं।

एनएच-44 पर घरौंडा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग का रोलआउट शुरू

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). भारत सरकार के निर्बाध, बाधा-रहित और प्रौद्योगिकी-संचालित राजमार्ग यात्रा के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग प्रणाली का पूर्ण पैमाने पर रोलआउट कर दिया है।

एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन एनएचएआई और इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल), एनएचएआई का तकनीकी अंग, द्वारा राकेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई चंडीगढ़ और ए. आर. चित्रांशी, मुख्य परिचालन अधिकारी, आईएचएमसीएल की उपस्थिति में किया गया। यह रोलआउट भारत के अगली पीढ़ी के टोलिंग बुनियादी ढांचे और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों की ओर संक्रमण में एक बड़ा मील का पत्थर है। एमएलएफएफ प्रणाली पारंपरिक टोल प्लाजा से एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो वाहनों को रुकने या धीमा होने की आवश्यकता के बिना टोल संग्रह को सक्षम बनाती है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) तकनीक का लाभ उठाते हुए ओवरहेड गैंट्री पर लगे उच्च-प्रदर्शन वाले सेंसर और कैमरे स्वचालित रूप से वाहनों की पहचान करते हैं और फास्टैग के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क काट लेते हैं।

डीसी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लिया जायजा

कहा, सुल्तानपुर लोधी के बुनियादी ढांचे और संपूर्ण विकास के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध

• **जालंधर ब्रीज.** सुल्तानपुर लोधी

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर अकाश बांसल ने आज सुल्तानपुर लोधी में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रोजेक्ट को बिना किसी देरी के निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए पूरा किया जाए। कपूरथला इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन एवं अर्जुन अवार्डी सज्जन सिंह चीमा, एस.डी.एम. जसजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी के एक्सियन विशाल जांगड़ाल, सीवरेज बोर्ड, पेडा, शिक्षा विभाग, नगर परिषद तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में डिप्टी कमिश्नर ने शहर में चल रही प्रमुख बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा की।

सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) में चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि इसे निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य अगले तीन महीनों में पूरा होने की संभावना है।

सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां) में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दो कक्षाओं के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, क्योंकि स्कूल की मुख्य इमारत तैयार हो चुकी है और वहां कक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने इसके संचालन और रखरखाव की समीक्षा की तथा कार्यक्षमता में सुधार के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने एक्सियन सीवरेज को निर्देश दिए कि एस.टी.पी. को इस माह के अंत तक चालू किया जाए। उन्होंने इस सुविधा में लगाए जा रहे सोलर पावर प्लांट की प्रगति का भी जायजा लिया तथा पेडा अधिकारियों को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने जब्बोवाल रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा कर वहां चल रहे लंबित विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम तथा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आई.सी.सी.सी.) की साइटों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य की गति तेज करने के लिए कहा। नगर परिषद द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए स्थानों की पहचान भी कर ली गई है। दौरे के दौरान उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को शहर में शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान का चयन करने के निर्देश दिए।

भाजपा प्रवक्ताओं का कांग्रेस नेता बेरी पर तीखा हमला

9 साल तक कांग्रस और आप के विधायकों नेताओं ने कुछ नहीं किया

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

जालंधर भाजपा महामंत्री अशोक सरीन हिक्की ने गुरुनानक पूरा इलाके के मंडल प्रधान संदीप कुमार, जालंधर भाजपा के प्रवक्ता सनी शर्मा, डिंपी लुभाना, बृजेश शर्मा और हिमांशु शर्मा के साथ जालंधर कांग्रेस के प्रधान केंद्रीय विधानसभा से पूर्व विधायक राजिंदर बेरी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गुरु नानक पुरा फ्लाईओवर के मुद्दे पर बेरी अपनी पुरानी राजनीतिक नाकामी को उपलब्धि बताने का निराधार, हास्यास्पद और जनता को गुमराह करने वाला प्रयास कर रहे हैं। हिक्की ने कहा कि सच यह है कि इस फ्लाईओवर का प्रस्ताव पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया द्वारा भेजा गया था और इसकी मंजूरी भी केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय ने दे दी थी, लेकिन 2017 से 2026 तक कांग्रस और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली नगर निगम जालंधर और पंजाब सरकार ने अपने हिस्से की बनती राशि जमा करवाने जारी करने की जिम्मेदारी नहीं निभाई। अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कि जब फाइलें मंजूर थीं, तब आठ साल तक पंजाब सरकार और नगर निगम ने जनता की सुविधा के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को क्यों लटकाए रखा? अगर केंद्र की मंजूरी थी तो काम क्यों नहीं हुआ? इसका सीधा जवाब है—कांग्रेस और उसके बाद पंजाब की सत्ता में बैठे लोगों की लापरवाही, इच्छाशक्ति की कमी और जनता के हितों के प्रति घोर उदासीनता। हिक्की ने कहा कि अब स्थिति यह है कि इन फ्लाईओवरों का पूरा खर्च केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय उठाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार और नगर निगम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे।

सीएम मान के कथित वीडियो मामले में हुई गिरफ्तारियां गंभीर : विजय सांपला

कहा- श्री अकाल तख़्त साहिब को चुनौती देना मान की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विजय सांपला ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वीडियो से जुड़े फ़र्ज़ी फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट मामले में गुरुग्राम में दर्ज एफआईआर तथा हुई गिरफ्तारियों ने पंजाब सरकार और उसके प्रतिनिधियों द्वारा किए गए अनेक दावों पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। श्री अकाल तख़्त साहिब के हुकमनामे को झूठा साबित करने के लिए कथित रूप से धन और प्रभाव का इस्तेमाल कर मनगढ़ंत फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाने की साज़िश का सामने आना अत्यंत गंभीर मामला है। सांपला ने कहा कि यदि जांच में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल कानून और जांच प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी का मामला नहीं होगा, बल्कि सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख़्त साहिब की मर्यादा और सर्वोच्चता को ठेस पहुंचाने का एक सुनियोजित प्रयास भी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख़्त साहिब सिख कौम की सर्वोच्च और शाश्वत संस्था है तथा यहां से जारी होने वाले हुकमनामे समस्त सिख समुदाय के लिए सम्माननीय और मान्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न आसीन हो, श्री अकाल तख़्त साहिब की मर्यादा से ऊपर नहीं हो सकता। विजय सांपला ने कहा कि सिंह साहिबानों के आदेशों की अवहेलना करके और श्री अकाल तख़्त साहिब की सर्वोच्चता को चुनौती देकर भगवंत मान ने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। सिख इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने भी अहंकारवश श्री अकाल तख़्त साहिब से टकराने का प्रयास किया, उन्हें न तो पंथ में सम्मान मिला और न ही इतिहास ने उन्हें क्षमा किया। उन्होंने कहा कि "विनाश काले विपरीत बुद्धि" की कहावत वर्तमान घटनाक्रम पर पूरी तरह लागू होती है। सत्ता के अहंकार में पंथक भावनाओं, धार्मिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को चुनौती देने वाली राजनीति का अंत निश्चित होता है। पंथ और पंजाब विरोधी सोच कभी भी जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती।

सांपला ने कहा कि पंजाब की जनता और समस्त सिख संगत यह जानना चाहती है कि आखिर ऐसी कौन-सी आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी कि एक धार्मिक और पंथक मामले में फ़ॉरेंसिक रिपोर्टों को प्रभावित करने के आरोप सामने आ रहे हैं।

केंद्रीय विधानसभा के हर रेलवे क्रॉसिंग का स्थायी समाधान भाजपा ही करेगी : राकेश राठौर

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

जालंधर के पूर्व मेयर एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजिंदर बेरी द्वारा गुरु नानक पुरा रेलवे ओवरब्रिज को लेकर दिए गए बयानों को तथ्यों से परे और जनता को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों पर झूठा श्रेय लेने की कांग्रेस की राजनीति अब जनता के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। राकेश राठौर ने कहा कि गुरु नानक पुरा रेलवे ओवरब्रिज का प्रोजेक्ट वर्ष 2017 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मंजूर हुआ था। उस समय इस परियोजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से पूरा किया जाना था। लेकिन इसके बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य सरकार ने अपने हिस्से का आवश्यक फंड जारी नहीं किया, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वर्षों तक लंबित पड़ा रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के बाद वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन उसने भी इस परियोजना को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

भारत-आयरलैंड के टी20 मैच का समय बदला

बेलफास्ट में खेले जाएंगे दोनों मैच, दोनों टीमों के बीच 2007 में खेला गया था पहला मैच

स्पोर्ट्स डेस्क. भारतीय टीम टी20 सीरीज के लिए आयरलैंड दौरे पर पहुंच गई है। शुक्रवार को दो मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला होगा। उससे ठीक पहले मैचों के समय में बदलाव कर दिया गया है। पहले दोनों मुकाबले स्थानीय समय अनुसार दोपहर ढाई बजे और भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होने थे। मैच के शुरू होने के समय को एक घंटा पीछे कर दिया गया है। अब दोनों ही मुकाबले भारत में शाम 6 बजे से ही शुरू हो जाएंगे। महिला टी20 विश्व कप के मुकाबले भी भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू हो रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत और आयरलैंड के बीच होने वाले मैचों के समय में बदलाव किया गया है। आयरलैंड क्रिकेट की तरफ से यह जानकारी दी गई है। भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 26 जून जबकि दूसरा 28 जून को खेला जाएगा। दोनों मैच बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले जाएंगे।

फोटो-बीसीसीआई

महिला टी20 विश्व कप के अहम मुकाबले में रविवार को भारतीय महिला टीम भी मैदान पर होगी। हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होनी है। सेमीफाइनल के रेस के लिए यह मैच काफी अहम होने वाला है। अभी तक भारत के ग्रुप से कोई भी टीम सेमीफाइनल में नहीं गई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम भी रेस में है।

भारत और आयरलैंड के बीच 2007 में पहला मैच हुआ था। अभी तक दोनों टीमों की टक्कर 11 मैचों में हो चुकी है। इसमें सभी मैच भारत ने जीते हैं। इस सीरीज में टीम इंडिया को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। मार्च में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय टीम की यह पहली टी20 सीरीज है।

फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट ने मान सरकार की साज़िश का पर्दाफाश किया; मुख्यमंत्री तुरंत इस्तीफा दें : बाजवा

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विवादित वीडियो के मामले में पंजाब सरकार ने फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाकर पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की। बाजवा ने कहा कि कथित रूप से झूठी फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल करने का प्रयास सरकार के बचाव के सभी दावों को ध्वस्त कर देता है और इससे जनता का यह संदेह और मजबूत हुआ है कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति वास्तव में भगवंत मान ही था। उन्होंने कहा कि आरोपों का पारदर्शी तरीके से सामना करने के बजाय सरकार ने कथित तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ कर एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ने का प्रयास किया ताकि मुख्यमंत्री को जवाबदेही से बचाया जा सके। बाजवा ने कहा, "फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती थी। यदि भगवंत मान निर्दोष थे, तो फोरेंसिक जांच को प्रभावित करने या उसमें हेरफेर करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? यह केवल धोखे का मामला नहीं है, बल्कि सत्ता और सरकारी तंत्र के घोर दुरुपयोग का उदाहरण है।"

उन्होंने कहा कि यह विवाद अब केवल वीडियो तक सीमित नहीं रहा है। यह मामला अब न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने, तथ्यों को दबाने और पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कथित साजिश में बदल चुका है। मुख्यमंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए बाजवा ने कहा कि भगवंत मान ने कथित तौर पर दुनियाभर के सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, J7 NEAR BUS STAND SUBHANPUR (HAMIRA), KAPURTHALA, PUNJAB - 144808, and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.